RAJYA SABHA

Friday, 7th May, 2010/17th Vaisakha, 1932 (Saka)

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR, CHAIRMAN: Question 601.

SHRI SITARAM YECHURY: The Opposition is missing, Sir! What is the reason?

DR. V. MAITREYAN: Principal Opposition! We are also Opposition. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Do you have any problem with that?

SHRI SITARAM YECHURY: No, no; I find it strange, Sir. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Question 601. Mr. Kaptan Singh Solanki.

माध्यमिक शिक्षा हेत् छात्राओं को प्रोत्साहन योजना

†*601. श्री कप्तान सिंह सोलंकी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) सरकार द्वारा देश में चलाई जा रही राष्ट्रीय छात्रा माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;
 - (ख) क्या यह योजना विफल रही है;
 - (ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
 - (घ) यदि नहीं, तो इसकी राज्यवार स्थिति क्या है?

मानव **संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल**): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) "माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना" जून, 2008 में प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन एवं स्कूल में बनाए रखने संबंधी स्थिति में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत (i) कक्षा ∨III की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सभी अ.जा./अ.ज.जा. बालिकाओं और (ii) उन बालिकाओं जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कक्षा ∨III की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद (इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे अ.जा. अथवा अ.ज.जा. की हैं) शैक्षिक वर्ष 2008-09 से किसी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त अथवा स्थानीय निकाय के विद्यालयों में कक्षा IX हेतु नामांकन करवाया हो, के नाम से 3000 रु. की राशि जमा कराई जाती है। वर्ष 2008-09 में दाखिले हेतु 25 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की 4,09,580 बालिकाओं को प्रोत्साहन देने हेतु 122.87 करोड़ रु. की राशि संस्वीकृत की गई। वर्ष 2009-10 में दाखिले हेतु 11 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की 83,187 पात्र बालिकाओं हेतु 24.94 करोड़ रु. की राशि संस्वीकृत की गई है।

[†]Original notice of the question was received in Hindi.

- (ख) तथा (ग) जी, नहीं। इस योजना के तहत संस्वीकृतियां राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने पर निर्भर होती हैं।
- (घ) बालिकाओं की संख्या के ब्यौरे सहित वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में दाखिले हेतु पात्र बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों हेतु संस्वीकृत राशि का राज्यवार विवरण-1 और ॥ में दिया गया है।

विवरण-। वर्ष 2008-09 के दौरान दाखिले हेतु 'माध्यमिक शिक्षा हेतु छात्राओं को प्रोत्साहन योजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम, पात्र बालिकाओं की संख्या तथा संस्वीकृत राशि

क्र.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पात्र बालिकाओं की	जारी की गई कुल
सं.	का नाम	कुल संख्या	राशि (रु. में)
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	2853	85,59,000
2.	बिहार	26105	7,83,15,000
3.	छत्तीसगढ़	24590	7,37,70,000
4.	गोवा	610	18,30,000
5.	गुजरात	44410	13,32,30,000
5.	हिमाचल प्रदेश	2176	65,28,000
7.	जम्मू और कश्मीर	3699	1,10,97,000
3.	झारखंड	15806	4,74,18,000
9.	कर्नाटक	81190	24,35,70,000
10.	केरल	21829	6,54,87,000
11.	मेघालय	1715	51,45,000
12.	मिजोरम	2691	80,73,000
13.	नागालैंड	161	4,83,000
14.	पंजाब	30191	9,05,73,000
15.	राजस्थान	16074	4,82,22,000
16.	सिक्किम	552	16,56,000
17.	तमिलनाडु	121292	36,38,76,000
18.	त्रिपुरा	2965	88,95,000
19.	उत्तराखंड	218	6,54,000
20.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	82	2,46,000

1	2	3	4
21.	चंडीगढ़	339	10,17,000
22.	दादरा व नगर हवेली	818	24,54,000
23.	दमन व दीव	121	3,63,000
24.	दिल्ली	7567	2,27,01,000
25.	पुडुचेरी	1526	45,78,000
	कुल	4,09,580	122,87,40,000

विवरण-॥

वर्ष 2009-10 के दौरान दाखिले हेतु 'माध्यमिक शिक्षा हेतु छात्राओं को प्रोत्साहन योजना' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम, पात्र बालिकाओं की संख्या तथा संस्वीकृत राशि

क्र.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पात्र बालिकाओं की	जारी की गई कुल
सं.	का नाम	कुल संख्या	राशि (रु. में)
l	गोवा	588	1764000
2.	झारखंड	18918	56754000
3.	जम्मू व कश्मीर	132 7	3981000
4.	केरल	22399	67197000
5.	मिजोरम	3270	9810000
5.	पंजाब	34524	103572000
7.	उत्तराखंड	60 7	1821000
3.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	157	471000
9.	चंडीगढ़	327	981000
10.	दमन व दीव	124	372000
11.	दादरा व नगर हवेली	886	2658000
	कुल	83127	249381000

Incentives to girls for secondary education

(a) the current status of National Scheme of Incentives to Girls for Secondary Education being run by Government in the country;

^{†*601} SHRI KAPTAN SINGH SOLANKI : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

[†]Original notice of the question was received in Hindi.

- (b) whether this scheme has failed;
- (c) if so, the reasons therefor; and
- (d) if not, the status thereof, State-wise?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

- (a) The "National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education" was launched in June, 2008 with the objective to Improve enrolment and retention of girls in the secondary stage. Under the scheme, an amount of Rs. 3000 is deposited in the name of (i) all SC/ST girls, who pass class VIII and (ii) girls who pass class VIII examination from Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (irrespective of whether they belong to Scheduled Castes or Tribes) and enrol for class IX in Government, Government aided or local body schools in the academic year 2008-09 onwards. A sum of Rs. 122.87 crore was sanctioned for grant of incentive to 4,09,580 eligible girls of 25 States/UTs for the admissions in 2008-09. For the admissions in the year 2009-10, an amount of Rs. 24.94 crore has been sanctioned for 83,127 eligible girls of 11 States/UTs.
- (b) and (c) No, Sir. The sanctions under the scheme depend upon the receipt of viable proposals from the States/UTs.
- (d) The State-wise details of the amounts sanctioned to various States/UTs for grant of incentive to eligible girls for admissions in 2008-09 and 2009-10 alongwith the details of the number of girls are given in the Statement-I.

Statement-I

Names of States/UTs, the number of eligible girls and the amount sanctioned under the Centrally Sponsored Scheme "Incentive to Girls for Secondary Education" for the admissions in 2008-09

SI.	Name of the State/UT	Total Number of	Total amount
No.		eligible girls	released (in Rs.)
1	2	3	4
1.	Arunachal Pradesh	2853	85,59,000
2.	Bihar	26105	7,83,15,000
3.	Chhattisgarh	24590	7,37,70,000
4.	Goa	610	18,30,000
5.	Gujarat	44410	13,32,30,000
6.	Himachal Pradesh	2176	65,28,000
7.	Jammu and Kashmir	3699	1,10,97,000
8.	Jharkhand	15806	4,74,18,000

1	2	3	4
9. K	Karnataka	81190	24,35,70,000
10. K	(erala	21829	6,54,87,000
11. N	Meghalaya	17 15	51,45,000
12. N	<i>l</i> izoram	2691	80,73,000
13. N	lagaland	161	4,83,000
14. P	Punjab	30191	9,05,73,000
15. F	Rajasthan	16074	4,82,22,000
16. S	Sikkim	552	16,56,000
17. T	amil Nadu	121292	36,38,76,000
18. T	ripura	2965	88,95,000
19. U	Uttarakhand	218	6,54,000
20. A	andaman and Nicobar Islands	82	2,46,000
21 . C	Chandigarh	339	10,17,000
22. D	adra and Nagar Haveli	818	24,54,000
23. D	aman and Diu	121	3,63,000
24. D)elhi	7567	2,27,01,000
25. P	uducherry	1526	45,78,000
Т	OTAL:	4,09,580	122,87,40,000

Statement-II

Names of States/UTs, the number of eligible girls and the amount sanctioned under the Centrally Sponsored Scheme "Incentive to Girls for Secondary Education" for the admissions in 2009-10

SI. No.	Name of the State/UT	Total number of eligible girls	Total amount released (in Rs.)
1	2	3	4
1.	Goa	588	1764000
2.	Jharkhand	18918	56754000
3.	Jammu and Kashmir	13 27	3981000
4.	Kerala	22399	67197000
5.	Mizoram	3270	9810000

1	2	3	4
6.	Punjab	34524	103572000
7.	Uttarakhand	60 7	1821000
8.	Andaman and Nicobar Island	1 57	471000
9.	Chandigarh	32 7	981000
10.	Daman and Diu	124	372000
11.	Dadra and Nagar Haveli	886	2658000
	Total:	83127	249381000

श्री कप्तान सिंह सोलंकी: सभापित जी, 'राष्ट्रीय छात्रा माध्यमिक प्रोत्साहन योजना" बहुत अच्छी योजना है। इसमें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 1000 करोड़ रुपए की राशि सभी राज्यों को देने का वायदा भी किया गया है। यह योजना जितनी अच्छी है, उतना अच्छा इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, इसलिए उन बातों को ध्यान में रखकर, मैं शिक्षा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस योजना के क्रियान्वयन से संतुष्ट हैं? यह लगातार देखने में आ रहा है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल न होने के कारण जिन अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्राओं को यह प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए, वह राशि भी उनके खातों में जमा नहीं हो पा रही है। क्या यह सत्य है कि डेढ़, दो साल तक भी छात्राओं के जीरो बैलेंस वाले खातों में राशि भी जीरो ही है? अगर यह सत्य है तो इस योजना का अच्छी तरह से क्रियान्वयन न होने के क्या कारण हैं और मंत्री महोदय आगे क्या करना चाहते हैं?

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, the hon. Member has asked a very important question and I have to say that I too feel a little disappointed that the Scheme has not been implemented at the pace at which it should have been implemented, but I would like to, through you, Sir, inform the hon. Member that the fault fairly does not lie with anybody. The Scheme envisages, Sir, that proposals have to come from the State Government. When the proposals come from the State Government, the Centre, then, sends the money to the State Government, depending on the proposals. Then, the State Government has to go to every school, of the category that he has mentioned, which has to get the benefit, and, then, the names of girls, which class they are studying in, the father's name, the date of birth, all those details have to be collated by the State Government. Then, those details are sent to the State Bank of India and, then, the State Bank of India has to prepare the Fixed Deposit for each of those girls. This is a very elaborate exercise. We would like the State Governments to handle it, but the State Governments refuse. They say, "You handle it Centrally." Handling it Centrally is extremely time-consuming. Therefore, there has been this delay, and the hon. Member is absolutely right, Sir, we need to devise a new system, and I will, certainly, relook at this issue and see how things can be made more efficient. But I hope that the State Governments will collaborate with us to make it more efficient.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री कप्तान सिंह सोलंकी: सभापित जी, 1 अप्रैल, 2010 से देश में "शिक्षा का अधिकार" लागू हो चुका है और देश में महिला साक्षरता दर भी काफी कम है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसमें मध्य प्रदेश का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मैंने राज्यवार सूची भी मांगी थी कि कहां पर, कितनी छात्राओं को कितनी राशि दी जा रही है। मैंने राज्य और केंद्र शासित संघ राज्यों की जो सूची देखी है, उसमें कहीं पर भी मध्य प्रदेश का नाम नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त योजनाओं में इस प्रदेश को शामिल नहीं करने के क्या कारण हैं? मध्य प्रदेश के साथ यह जो पक्षपात किया जा रहा है, मंत्री जी उसके कारण बताने की कृपा करें?

SHRI KAPIL SIBAL: Through you, Sir, I would like to inform the hon. Member that the reason why Madhya Pradesh is not being mentioned is that Madhya Pradesh has never sent a proposal. So, if there is any discrimination, the discrimination lies to your end, Sir.

If you had sent a proposal, we would have certainly mentioned it.

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, it is a little disappointing that the Scheme has not yet taken off. But I am sure with the dynamic Minister at the helm this will start functioning. But my question is different. Apart from giving scholarships to girls, what is required is providing some facilities like small retiring room and separate toilets for girls in the schools. Unless you have separate toilets for girls, particularly religious people and even others are reluctant to send their girls. This huge sum of money you give to the girls certainly. Will you add on to this Scheme a small retiring room and separate toilets for girls in the schools? That will go a long way as an incentive for the girls to attend the schools.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, the hon. Member is absolutely right and this is the reason why under the Right to Education Act, this provision is provided and it is mandatory. All schools in India, whether public or private, have to have separate toilets for girls and once that is done, those infrastructure requirements are met, I think, the problem will be addressed. The private unaided schools will have to pay for it. The Government has to pay for the Government schools and the aided schools, of course, as you know, are aided by us. But this is an infrastructure requirement which is mandatory and that they have to comply with it. I would like to mention that now in the context of education, we are looking at the future of our children. We are looking at the future of India. I would request all the State Governments to give us their formal proposals, expedite those proposals and if there is any difficulty, come and contact me. I will personally look into it because this is a national mission that all of us have to undertake together.

SHRI M.V. MYSURA REDDY: Sir, this is a laudable Scheme. The Government also intends to educate the girls. But I want to know from the Minister whether the Scheme will be extended to all girls studying in the Government schools and aided schools. Secondly, you remove the restriction that girls passed the tenth standard only; then only they will get the incentive. What is

the reason for not removing them? Andhra Pradesh was also not mentioned in the list of the States to which the amount had been released.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, that all depends on what kind of formal proposal has been sent, whether it has been sanctioned or not. If it is not sanctioned, the amount will not be released. When we talk of extending this Scheme to all girls, if we are to extend it, there are — we tried to calculate it — about 59-60 lakh girls studying in the secondary sector. If we were to extend it, we would require more than Rs. 7,000 crores which is the budgetary provision. But under the Plan we have provided Rs. 1,500 crores. Naturally, we could not extend it to all the girls. So, with the limited provision of Rs. 1,500 crores in the Budget, we chose the SC&ST categories and the Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas. Therefore, we have extended this Scheme to them.

SHRI M.V. MYSURA REDDY: The amount is not released to Andhra Pradesh.

SHRI KAPIL SIBAL: As I have said, if Andhra Pradesh has not sent a formal proposal, the release will not be there. If it is sent, it is being scrutinized. The moment it is sanctioned, the release will be there.

PROF. P.J. KURIEN: Sir, we are happy that we have a very dynamic Minister. He is a Minister of principles. I am not asking that this Scheme should be extended to all girls. But my question is this. Why don't you consider extending it to the girls coming from the Below Poverty Line families? In Navodaya Vidyalayas, you are giving full scholarships to everybody. There are Central schools also. In the case of Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas you have already stated that it is given to all irrespective of caste and religion. Why don't you give it to poor girl students coming from all sections of Below Poverty Line? In this connection, I would like to submit that as far as girls' education is concerned, it is not only the SC and ST girls are suffering, but also girls from weaker sections and poorer sections in the rural areas are not being sent to schools. One of the reasons is what Dr. Karan Singh Sahib has said. Therefore, this is a question to which I would like to have an answer.

Earlier the MPs used to recommend two students. Mostly they were poor students. You have done away with that provision. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Question, please.

PROF. P.J. KURIEN: My question is: (1) Why don't you extend it to all girl students from BPL families? (2) Why don't you reconsider the MPs' quota?

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, so far as both the questions of the hon. Member are concerned, as I said, we, ultimately, can only extend the scheme with reference to the budgetary allocation that has been made. In the context of the budgetary allocation, we thought that we first target the SC and the ST categories and the Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas because those are in rural areas. Therefore, the weakest of the communities are targeted.

As far as the quota is concerned, I would like to mention and inform the hon. Members, through you, Sir, that yesterday I had an emergent meeting of the Kendriya Vidyalaya

Sangathan. I have decided, in the light of the sentiments expressed by the hon. Members, not just of the Rajya Sabha but also of the Lok Sabha, to restore the two nominations to each Member of Parliament. But as far as my own quota is concerned, I have surrendered it. I have not kept it. I have surrendered both my Minister's quota as well as my personal MP quota. But I have restored it for all of you.

DR. V. MAITREYAN: Sir, on behalf of the whole House, I thank the hon. Minister.

तालचेर और अंगुल में बन्द पड़ी उर्वरक इकाइयां

*602. श्री रुद्रनारायण पाणि: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के तालचेर और अंगुल उपखंडों में निर्मित परिसर में बंद पड़े उर्वरक कारखानों को प्रदूषण की आड़ में आगे नहीं चलाया जाएगा;
 - (ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;
 - (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
 - (घ) क्या सरकार अपने पहले के आश्वासन से मुकर रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जी, नहीं। मंत्रिमंडल के दिनांक 30.10.2008 के निर्णय के अनुसरण में फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एफसीआईएल) की तलचर इकाई सिहत बंद पड़ी सार्वजिनक क्षेत्र की उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार की व्यवहार्यता का पता लगाने का निर्णय लिया गया है, बशर्ते गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो, तािक देश में यूरिया के उत्पादन एवं मांग के बढ़ते अन्तर को पूरा किया जा सके। सिववों की एक अधिकार-प्राप्त सिमित का गठन किया गया है जिसका अधिदेश एफसीआईएल की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए सभी निवेश विकल्पों का मूल्यांकन करना और सरकार के विचारार्थ उचित सिफारिशें करना है।

सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति के निर्णयानुसार, व्यावसायिक परामर्शदाता मैसर्स डेलोयट ने राजस्व शेयरिंग मॉडल के आधार पर प्रस्तावित पात्रता और मूल्यांकन मानदंड प्रस्तुत कर दिए हैं।

तलचर के पुनरुद्धार के लिए, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् गैस अर्थोरिटी ऑफ इंडिया लि (गेल), कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ) के संघ के माध्यम से 22.12.2009 को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें एफसीआई, तलचर में कोयला आधारित प्रौद्योगिकी का उर्वरक संयंत्र लगाने का आशय व्यक्त किया गया है। कोल इंडिया लि. ने परियोजना के लिए कोयले की अबिधित आपूर्ति करने का आश्वासन दिया है और नामांकन के आधार पर परियोजना के आबंटन करने का अनुरोध किया है।

एफसीआईएल की बंद इकाईयों के पुनरुद्धार के संबंध में डेलोयट की सिफारिशों के साथ-साथ संघ द्वारा प्रस्तुत की सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच की जा रही है ताकि उर्वरक विभाग सरकार का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त कर सके।

पर्यावरणीय अनुमोदन के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने आरंभिक बैठक में इस परियोजना को अपना अनुमोदन नहीं दिया था क्योंकि तलचर में व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक हैं।